कवायद

चीन प्लस वन रणनीति के तहत 200 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से चल रही बातचीत

विदेश से बड़ा निवेश जुटाने के प्रयास में प्रदेश सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। सरकार का फोकस विदेश से पूंजी लाना और राज्य को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए योगी सरकार चीन प्लस वन की रणनीति पर काम कर रही है।

इस रणनीति के तहत अब तक करीब 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत की जा चुकी है। चीन प्लस वन लीड के तहत जिन देशों पर सबसे ज्यादा फोकस

सरकार विशेष टीम और देश विशेष के लिए डेस्क बनाने पर भी कर रही विचार

है, उनमें अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, डेनमार्क की कंपनियां शामिल हैं। इनमें अमेरिका से 30 से ज्यादा, जर्मनी से 30 के करीब, जापान से 20, चीन से 14, स्विट्जरलैंड और फ्रांस से 7-7, डेनमार्क से 6 और स्पेन से 5 कंपनियां शामिल हैं। इन देशों की कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छुक हैं। उनकी इच्छा को धरातल पर उतारने के लिए यूपी सरकार विशेष टीम और देश विशेष के लिए डेस्क बनाने पर भी विचार कर रही है।

निवेश प्रोत्साहन की पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कई और भी कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अब तक 574 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 70 कंपनियां पहले से ही उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इसके अलावा 11 कंपनियों के पास नए प्रोजेक्ट हैं। 20 कंपनियों ने सीधे यूपी सरकार के साथ एमओयू किया है। वहीं 473 कंपनियों के साथ सरकार लगातार संपर्क में है।

यह है चीन प्लस वन रणनीति

चीन प्लस वन रणनीति एक ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जिसे दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां अपनाती हैं। अब प्रदेश सरकार भी इस पर आगे बढ़ रही है। इसका उद्देश्य यह है कि ये कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सिर्फ चीन पर निर्भर न रखकर, एक या अधिक अतिरिक्त देशों में सेट करती हैं। उत्तर प्रदेश को इससे सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहां बड़ी जनसंख्या उपलब्ध है।